



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 1, 2015/आश्विन 9, 1937

No. 255]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2015/ASVINA 9, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 1, अक्टूबर, 2015

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन. गण. और चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नैरो वोवेन फेब्रिक के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत

सं. 15/14/2015-डीजीएडी.—यतः 1995 में और उसके बाद यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 9 जून, 2004 को चीन जन. गण. और चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नैरो वोवेन फेब्रिक के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जाँच की शुरुआत की थी और प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जाँच परिणाम 10 जनवरी, 2005 को जारी किए गए थे। अन्तिम शुल्क 14 फरवरी, 2005 को लगाया गया था। प्राधिकारी ने 7 जून, 2005 को अपने अंतिम जाँच परिणाम जारी किए जिनमें निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की गई और 25 जुलाई, 2005 की सीमा-शुल्क अधिसूचना द्वारा शुल्क लगाया गया था।

2. तत्पश्चात् प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या यदि पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है तो पाटन के होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क की अवधि को आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने 20 अगस्त, 2009 को संबद्ध देशों से नैरो वोवेन फेब्रिक के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत की। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 19 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या 15/9/2009-डीजीएडी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम जारी किए और केन्द्र सरकार द्वारा 6 अक्टूबर, 2010 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 108/2010 द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। शुल्क की अवधि 5 अक्टूबर, 2015 में समाप्त होगी।

क. निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करने के लिए अनुरोध

3. यतः सीमा-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो वह उसे लगाने की तारीख से पाँच वर्षों के पूरा होने पर समाप्त हो जाते हैं। संबंधित नियमावली में प्राधिकारी के लिए समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की समीक्षा करना अपेक्षित है और यदि वह उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर संतुष्ट हों कि ऐसे शुल्क को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार से उसे हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। उक्त उपबंध के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए उपाय की समाप्ति की तारीख से पहले तर्कसंगत अवधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत् रूप से साध्यांकित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

4. और यतः नैरो वोवेन फैब्रिक के घरेलू उत्पादक मै. इशी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) द्वारा अधिनियम और नियमावली के अनुसार एक याचिका दायर की गई है जिसमें उक्त देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया गया है और यदि पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है तो पाटन के जारी रहने और चीन जन. गण. और चीनी ताइपेई (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित नैरो वोवेन फैब्रिक (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

ख. समीक्षा के लिए आधार

5. लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध इन कारणों पर आधारित है कि चीन जन. गण. और चीनी ताइपेई से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है, उपाय समाप्त होने से इन देशों से पाटन के जारी रहने और उसके तेज हो जाने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की आशंका है। आवेदक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह दावा किया है कि इस तथ्य के बावजूद कि पाटनरोधी शुल्क लागू है संबद्ध देशों से निर्यातक भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन करना जारी रखा है।

6. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और यूएई से संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में पाटित कीमतों पर आयात किया जा रहा है। उन्होंने यह दावा किया है कि ये आयात चीन से ट्रांसशिपमेंट हैं क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया और यूएई में संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए कोई ज्ञात विनिर्माण सुविधा नहीं है।

7. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के निर्यातकों की उत्पादन क्षमता और उनके उच्च निर्यातोन्मुख होने पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है और यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो इससे पाटन की पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की आशंका है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

8. दिनांक 7 जून, 2005 की नैरो वोवेन फैब्रिक की मूल जाँच की अंतिम जाँच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार वर्णित है:

‘2. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद ‘मानव निर्मित फाइबर से निर्मित पाइल वीव वाला नैरो वोवेन फैब्रिक है, जिसका प्रयोग फास्टेनिंग टेप के रूप में किया जाता है’ (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है)। बाजार शब्दावली में संबद्ध वस्तु को अनेक पर्यायवाची जैसे ‘हुक एंड लूप टेप फास्तेनर’, ‘वेलक्रो टेप्स’, ‘फास्टेनिंग टेप्स’, ‘फास्तेनर’ आदि जाना जाता है। इस उत्पाद की विशिष्ट विशेषता ‘पाइल वीव’ है। संबद्ध वस्तु को फील मजबूती, शीयर मजबूती और लाइट फास्तेनेस के अनुसार वर्णित किया जाता है। हुक और लूप फास्तेनर आम तौर पर मानव-निर्मित फाइबर (यार्न) नाइलोन (नाइलोन 6 और नाइलोन 6,6) पालिएस्टर आदि से निर्मित होते हैं। विचाराधीन उत्पाद 12 मिमी. से 125 मिमी. की चौड़ाई के बीच विशिष्ट रूप से आकारों में उत्पादित होती है। इसके अलावा, यद्यपि उत्पाद को बाजार में उत्पाद की लम्बाई (मीटर में मापित) में बेचा जाता है और उत्पाद के विभिन्न प्रकारों की लागत और कीमत चौड़ाई के अनुसार भिन्न होती है, तथापि भार में परिवर्तित होने पर यह लगभग समान हो जाते हैं। संबद्ध वस्तु के प्रमुख उपयोग परिधान उद्योग, शल्य चिकित्सा और आर्थोपेडिक उपकरण विनिर्माण, जूते और फुटवियर विनिर्माण, सामान/बैग विनिर्माण, खिलौना, आटोमोबाइल अपहोल्स्टरी और विभिन्न अन्य औद्योगिक खंडों जैसे उद्योगों में होता है। नैरो वोवेन फैब्रिक को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा-शुल्क उप शीर्ष 580610 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनंतिम जाँच परिणामों के बाद, मै. कंट्रीक्राफ्ट आयातक ने प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या जाँच केवल हुक और लुक टेप के संबंध में की गई है जबकि अधिसूचना में पूरे अध्याय का उल्लेख है। प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि पाटनरोधी जाँच केवल यथोक्त विचाराधीन उत्पाद (जिसे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के संबंध में की गई है और

जैसा जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना और प्रारंभिक जाँच परिणाम में उल्लेख है और तथापि सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

9. निर्णायक समीक्षा जाँच होने के कारण वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद मूल जाँच में परिभाषित उत्पाद के समान ही रहेगा।

10. आवेदक ने अनुरोध किया है कि उनके द्वारा उत्पादित नैरो वोवेन फैब्रिक संबद्ध देशों से आयातित नैरो वोवेन फैब्रिक से भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के अनुसार समान वस्तु है। आयातित उत्पाद और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और उपभोक्ता इनका प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं।

11. विचाराधीन उत्पाद को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 58 के सीमा-शुल्क उप शीर्ष 580610 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग

12. निर्णायक समीक्षा हेतु याचिका मै. इशी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। आवेदक के अलावा, संबद्ध वस्तुओं को मैजिक फास्टेनर्स प्रा. लि., स्काई इंडस्ट्रीज लि., सिद्धार्थ फिलामेंट प्राइवेट लिमिटेड, गजानंद इलास्टिक लेस वर्क्स और रिया टेक्स फैब प्रा. लि. द्वारा उत्पादित किया जाता है। मैजिक फास्टेनर्स प्रा. लि. और स्काई इंडस्ट्रीज लि. ने याचिका का समर्थन किया है। आवेदक द्वारा उनकी बाजार आसूचना के अनुसार अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादकों के उत्पादन के संबंध में सूचना प्रदान की गई है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक का भारत में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा (49 प्रतिशत) बनता है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। अतः प्राधिकारी आवेदक को पात्र घरेलू उद्योग मानते हैं।

ङ. शामिल देश

13. चीन जन. गण. और चीनी ताइपेई के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लागू है। दोनों देशों से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और परिणामी क्षति होने के आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के मद्देनजर इस निर्णायक समीक्षा में चीन जन. गण. और चीनी ताइपेई दोनों शामिल होंगे।

च. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

14. समीक्षा की जरूरत को सही ठहराते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार समीक्षा की शुरुआत करते हैं ताकि इस बात की समीक्षा की जा सके कि क्या नैरो वोवेन फैब्रिक के आयातों पर 6 अक्टूबर, 2010 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 108/2010 द्वारा लगाये गए शुल्क के हटने से चीन जन. गण. और चीनी ताइपेई से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रहेगा या उसकी पुनरावृत्ति होगी और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी और क्या संबद्ध वस्तु के विरुद्ध लागू निश्चयात्मक शुल्क को जारी रखने की जरूरत है।

छ. प्रक्रिया

15. इस जाँच से यह निर्धारित होगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है। प्राधिकारी इस बात की जाँच करेंगे कि क्या पाटन की क्षतिपूर्ति के लिए ऐसे शुल्क को जारी रखने की जरूरत है और क्या यदि शुल्कों को हटाया या बदला जाता है या ये दोनों किए जाते हैं तो क्षति होना जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(i) इस समीक्षा में चीन जन. गण. और चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नैरो वोवेन फैब्रिक के लिए दिनांक 19 अगस्त, 2010 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना के सभी पहलू शामिल होंगे।

(ii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015 तक की अवधि जाँच अवधि (पीओआई) के रूप में है। तथापि, क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014 और जाँच अवधि के आकड़ों पर विचार किया जाएगा। (iii) संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय****वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय****वाणिज्य विभाग****चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग****संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001**

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उक्त अनुरोध का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा।

झ. समय-सीमा

18. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

ज. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप से अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनके साथ उनकी सॉफ्ट कापियाँ होनी चाहिए।

21. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पाँच (5) प्रतियां सॉफ्ट प्रतियों के साथ, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

22. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु; सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक

परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार का उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ठ. असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2015

(Sunset Review Investigation)

Subject : Initiation of Second Sunset Review of the antidumping duty in force on imports of Narrow Woven Fabric originating in or exported from China PR and Chinese Taipei.

F. No. 15/14/2015/DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated an anti-dumping investigation against import of Narrow Woven Fabric originating in or exported from China PR and Chinese Taipei on 9th June, 2004 and preliminary findings were issued by the Authority on 10th January, 2005. Provisional duties were imposed on 14th February, 2005. The Authority issued its final findings on 7th June, 2005 recommending imposition of definitive duties and duties were imposed vide customs notification dated 25th July, 2005.

2. Thereafter, the Authority examined whether cessation of anti-dumping duty was likely to lead to dumping and consequent injury to the domestic industry and whether the anti-dumping duties were required to be extended further. The Authority initiated sunset review investigations on imports of Narrow Woven Fabric from the subject countries on 20th August, 2009. The Designated Authority issued Final Findings vide Notification No. 15/9/2009-DGAD dated 19th August, 2010 and definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 108/2010 dated 6th October, 2010 for a period of five years. The duties shall expire on 5th October, 2015.

A. Request for initiation of Sunset Review

3. WHEREAS in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Rules made thereunder, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition. The Rules supra require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of anti-dumping duty and if it is satisfied, on the basis of information received by it that, there is no justification for continued imposition of such duty, the Authority may recommend to the Central Government for its withdrawal. Notwithstanding the above provision the authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. And Whereas a petition has been filed by the domestic producer of Narrow Woven Fabric, M/s. Ishi Industries Limited (hereinafter referred to as applicant) in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the above goods, originating in or exported from the above countries and consequent injury to the domestic industry and requesting for initiating a sunset review investigation for continuation of anti-dumping duty in force on imports of Narrow Woven Fabric (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR and Chinese Taipei (hereinafter referred to as the subject countries).

B. Grounds for review

5. The request is for continuation of the anti-dumping duties in force based on the grounds that dumping of the subject goods has continued from China PR and Chinese Taipei, the expiry of the measure would be likely to result in continuation and intensification of dumping from these countries and consequent injury to the domestic industry. The applicant has, inter-alia, claimed that the exporters from the subject countries continued to dump the subject goods in the Indian market, in spite of the anti-dumping duty in force.

6. The applicant has further claimed that the subject goods are being imported from Indonesia, Malaysia and UAE in significant volumes and at dumped prices. They have claimed that these imports are transshipments from China as there is no known manufacturing facility to produce the subject goods in Indonesia, Malaysia and UAE.

7. The applicant has claimed that there is a likelihood of recurrence of dumping from the subject countries, considering the production capacity and high export orientation of the exporters of the subject goods, and that would lead to recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry, if the anti dumping duties are revoked.

C. Product under consideration and like Article

8. The product under consideration in the Final Findings of the original investigation of Narrow Woven Fabric dated 7th June, 2005 was described as follows:

"2. The Product under consideration in the present investigations is "narrow woven fabric having pile weave, made up of manmade fibers, used as a fastening tape" (henceforth also referred to as subject goods). In market parlance, the subject goods are known by various synonyms such as "Hook & Loop Tape Fasteners", "Velcro Tapes", "Fastening Tapes", "Fasteners" etc. The distinguishing feature of the product is "pile weave". The subject goods are described in terms of Peel Strength, Shear Strength and Light Fastness. Hook and Loop fasteners are generally made from manmade fibers (yarns) nylon (Nylon 6 and Nylon 6,6), polyester etc. The product under consideration is produced in sizes typically varying between 12mm to 125mm of width. Further, while the product is sold in the market place in terms of length of the product (measured in meters) and the associated costs and prices of various product types vary with width, the same becomes almost homogenous when converted into weight. The major uses of the subject goods are in industries such as garment industries, surgical & orthopedic apparatus manufacturing, shoes & footwear manufacturing, luggage/bags manufacturing, toys, automobile upholstery and various other industrial segments. Narrow Woven fabric is classified under customs Sub heading 580610 of the Customs Tariff Act, 1975. After the provisional findings, M/s Country Craft, importer, asked the Authority to clarify whether the investigation has been performed only on hook and loop tape, whereas the notification mentions the entire chapter. The Authority confirms that Anti-dumping investigations have been conducted with regard to the product under consideration only as mentioned above (also referred to as subject goods) and as stated in the initiation notification, as well as in the preliminary findings, and the customs classification is indicative in nature and is in no way binding on the scope of the investigation."

9. Present investigation being a sunset review investigation, the product under consideration would remain the same as has been defined in the original investigation.

10. Applicant has submitted that Narrow Woven Fabric produced by them is like article to Narrow Woven Fabric imported from the subject countries in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The imported product and the domestically produced goods are technically and commercially substitutable, and consumers use them interchangeably.

11. The product under consideration is classified under Chapter 58 of the Custom Tariff Act under the subheadings 580610. However, the customs classification is indicative in nature and is in no way binding on the scope of the investigation.

D. Domestic industry

12. The petition for the sunset review has been filed by M/s. Ishi Industries Limited. Apart from the applicant, the subject goods are produced by Magic Fasteners Pvt. Ltd., Sky Industries Ltd., Sidhartha Filaments Private Limited, Gajanand Elastic Lace Works and Riya Texfeb Pvt. Ltd. Magic Fasteners Pvt. Ltd. and Sky Industries Ltd. have supported the petition. The information regarding the production of the other known Indian producers has been provided by the applicant as per their market intelligence. It is noted that the production of the applicant constitutes a major proportion (49%) of total domestic production of subject goods in India. It is also noted that the applicant has not imported the subject goods nor are they related to any importer or exporter from the subject countries. The Authority has, therefore, considered the applicant as eligible domestic industry.

E. Countries involved

13. The anti-dumping duties are in force against China PR and Chinese Taipei. In view of the *prima facie* evidence of continuation or recurrence of dumping from both the countries and consequent injury as provided by the applicant, the sunset review will cover both China PR and Chinese Taipei.

F. Initiation of Sunset Review

14. Having satisfied itself on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry, substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a review in accordance with Section 9 a (5) of the Act, read with Rule 23 of Anti-dumping Rules, to review whether revocation of the duty, imposed vide Customs Notification No. 108/2010 dated 6th October, 2010 on imports of Narrow Woven Fabric, shall lead to continuation or recurrence of dumping of the subject goods from China PR and Chinese Taipei and continuation or recurrence of injury to the domestic industry and need for continued imposition of the definitive duty in force against the subject goods.

G. Procedure

15. The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duties were removed or varied, or both.

- (i) The review will cover all aspects of Final Finding Notification dated 19th August, 2010 for Narrow Woven Fabric originating in or exported from China PR and Chinese Taipei;
- (ii) The period of investigation for the purpose of the present review is from April 2014 – March, 2015 (POI). However, for the purpose of analyzing injury, the data of 2011-12, 2012-13, 2013-14 and the POI shall be considered;
- (iii) The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

H. Submission of Information

16. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
4th Floor Jeevan Tara Building, Parliament Street
New Delhi-110001**

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

I. Time Limits

18. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

J. Submission of information on confidential basis

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

K. Inspection of public file

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

L. Non-cooperation

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Designated Authority